Statement

Information received from various States/UTs in respect of the implementation of the Instructions/ Guidelines issued in pursuance of the Supreme Court Judgement on identifications of Creamy Layer

S.No.	Name of State/UT	Contents of the reply
1.	Andaman & Nicobar Islands	The UT Administration has not implemented the Guidelines/Instructions issued by the Govt. because this UT has not identified the OBC in the U.T.
2.	Jammu & Kashmir	The Government have implemented the Guidelines/ Instructions issued by the Government in this regard. The State Govt. has sanctioned J&K Reservation Rules 1994, vide 126 of 1994 regarding the reservations to OBCs in the admission of professional institutes & recruitment of Govt. Services.
3.	Andhra Pradesh	The Government have implemented the instructions/ guidelines issued by the Govt. of India in this regard vide this Government's Memo No. 3047/P-2/94-4 dated 28.3.1994.
4.	Maharashtra	This Government have implemented the instructions/ guidelines issued by the Govt. of India in this regard vide Govt.'s resolutions No. CBC-1094/CR-86/BCW-V dated 16.6.94.

गद्दी और गूजर समुदायों को अभी तक भी अनुसूचित जनजाति घोषित न किया जाना

1017. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में जिला कांगडा, कुल्लू, ऊना आदि के गद्दी और गूजर समुदाय के उन लोगों को जिन्हें पंजाब के पुनर्गठन के उपरान्त हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया था, अभी तक भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य घोषित नहीं किया गया है;

(ख) क्या चम्बा, मंडी-सिरमौर आदि जिसे पुराना हिमाचल कहा जाता है, में रहने वाले गद्दी और गूजर समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति का सदस्य घोषित किया गया है;

(ग) उपरोक्त विसंगति को दूर करने के लिए सरकार को भिन्न-भिन्न जन-जातियों से कब-कब अनुरोध प्राप्त हुए; और

(घ) सरकार द्वारा उन पर आज तक क्या कार्यवाही की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया): (क) [illegible]

(ग) हिमाचल प्रदेश के गद्दी तथा गूजर समुदायों से संबंधित क्षेत्रीय प्रतिबन्ध को हटाने के लिए पिछले कई वर्षों से दावे प्राप्त किए जा रहे हैं।

(घ) यह प्रस्ताव विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूचियों में संशोधन के लिए अन्य ऐसे दावों के साथ सरकार के विचाराधीन हैं।

Increasing cases of starvation deaths in Orissa

1018. SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the increasing cases of starvation deaths in various parts of Orissa as reported in the newspapers;

(b) if so, the details thereof in last six months, month-wise and district-wise;

(c) the immediate steps including time bend plan Central Government has taken to remedy the situation;

(d) the amount of Central assistance if any, released for Orissa to meet the requirement